भारतीय शहरों को बचाने की मुहिम

गिरिराज अग्रवाल

इंदौर में हुए शहरी प्रबंधन के नए प्रयोग

भारत का आधे से ज़्यादा आर्थिक विकास शहरों पर निर्भर है जिनमें लगभग 30 करोड़ लोग रहते हैं। ऐसा आकलन है कि वर्ष 2030 तक भारत की आधी आबादी शहरों में रहने लगेगी। इससे नागरिक सुविधाओं पर और ज़्यादा बोझ पड़ेगा।

इस समस्या का हल तलाशने के लिए अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी यूएसएड भारतीय शहरों को शहरी प्रबंधन के नए तरीके सीखने में मदद कर रही है। यूएसएड की शहरी प्रबंधन परियोजना ने स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण और तकनीकी मदद मुहैया कराई है जिससे कि वे अपना राजस्व बढ़ा सकें, ज़्यादा बेहतर प्रबंधन कर सकें और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकें।

यूएसएड की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिफार्म्स एंड एक्सपेंशन-डेब्ट पहल इस बात का उदाहरण है कि कैसे सही दिशा में किए गए प्रयास एक शहर में नागरिक सुविधाओं के विकास में सकारात्मक पहल कर सकते हैं। आज से दस साल पहले तक इंदौर में नागरिक सुविधाओं का जिम्मा उठाने वाले इंदौर नगर पालिक निगम के पास शहर की बेहद ज़रूरी नागरिक सुविधाओं तक के लिए राजस्व नहीं जुटता था जिससे निगम अधिकारी शहर की दिनोंदिन बढ़ती आबादी के लिए मूल सुविधाओं का विस्तार करने और नई सुविधाएं जुटाने के बारे में सोच भी नहीं पाते थे। यूएसएड परियोजना के शहरी प्रबंधन सलाहकार चेतन वैद्य बताते हैं, ''सड़कों की हालत खराब हो रही थी, पानी की बढ़ती ज़रूरत के लिए योजनाओं पर अमल करने को पैसा नहीं था और निगम और नागरिकों के बीच किसी तरह की ठोस भागीदारी नहीं थी जिसके चलते इंदौर को बेहतर बनाने का कोई सपना आकार नहीं ले रहा था।''

लेकिन फिर निगम के शीर्ष नेतृत्व ने परिस्थितियों को बदलने की इच्छा शक्ति दिखाई और वर्ष 2000 में भविष्य का खाका तैयार किया गया। सोचा गया कि कैसे राजस्व बढ़ सकता है, किस तरह नागरिकों को विकास योजनाओं में भागीदार बनाया जा सकता है, किस तरह राज्य और केंद्र से ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान लिया जा सकता है और किस तरह निगम की छवि सुधार कर नागरिक सुविधाओं की नई योजनाओं के लिए बाज़ार से पैसा जुटाया जा सकता है। बदलाव की इच्छाशक्ति जगी तो निगम को अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास सहायता एजेंसी से संबद्ध शहर प्रबंधन परियोजना के रूप में मददगार भी मिल गया और 2003 में इस पर अमल शुरू हुआ। इस संस्था ने मध्य प्रदेश में नगर प्रबंधन बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी मदद दी जिससे नगर प्रबंधकों के रवैये में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला और खासकर इंदौर नगर पालिक निगम ने राजस्व जुटाने से लेकर नागरिक सुविधाओं की योजनाओं को शुरू करने में तेज़ी दिखाई।

इंदौर किस तरह बदला है, इसका आकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि 1997 में निगम अपने स्रोतों से जहां महज लगभग 16 करोड़ रुपये सालाना जुटा पाया था, वहां अब पिछले वित्त वर्ष में उसने 92 करोड़ रुपये जुटाए। मध्य प्रदेश सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन के समन्वयक आशीश अग्रवाल कहते हैं, ''राजस्व के छह गुना होने में सबसे कारगर हथियार साबित हुआ बेहतर प्रबंधन। यूएसएड परियोजना के तहत प्रशिक्षण... से शहरी प्रबंधकों के रवैए में बदलाव आया। वे प्रबंधन के बेहत तरीकों में दिलचस्पी लेने लगे जिससे निगम की आय में इजाफ़ा हुआ।''

इंदौर की मेयर डॉ. उमा शशि शर्मा बताती हैं, ''निगम ने अपनी बेहतर स्थिति के चलते 60 से 80 साल की उम्र के सभी इंदौरवासियों के लिए 20 हज़ार तक का चिकित्सा बीमा कराया है। इसी तरह की एक अन्य योजना में सभी नागरिकों का दस हज़ार रुपये का दुर्घटना विकलांगता बीमा कराया गया है।

इंदौर में नगर पालिक निगम की बेहतर वित्तीय स्थिति के चलते अब निगम कई तरह की नागरिक सुविधाओं की योजनाओं पर अमल कर रहा है। नर्मदा सागर से मार्च 2009 तक पानी लाने के लिए 641 करोड़ रुपये की योजना पर अमल हो रहा है। नगर पालिक निगम शहर में अब तक 150 पार्क विकसित कर चुका है जो रहवासी संघों की देखरेख में चल रहे हैं। इसी तरह शहर में आम लोगों के लिए नगर बस सेवा शुरू की गई है। इसके तहत 864 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इस योजना में नब्बे से ज़्यादा लो फ्लोर बसें फिलहाल शहर में चल रही हैं जो विकलांगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। शहर में झुग्गी बस्तियों को कम करने के लिए मकान बनाए जा रहे हैं।

इन सभी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन से 50 फ़ीसदी धनराशि मिल रही है। इस मिशन के तहत शहरों में नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए सुधार कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार 20 फ़ीसदी का योगदान करेगी जबकि बाकी की 30 फ़ीसदी राशि का इंतजाम खुद निगम को अपने स्रोतों से करना होगा। वैद्य कहते हैं, ''यदि यूएसएड परियोजना ने निगम की वित्तीय हालत सुधारने को प्रोत्साहन नहीं दिया होता तो वह इस मिशन के तहत बड़ी परियोजनाओं का जिम्मा नहीं ले पाता।''

इंदौर नगर निगम ने कर प्रणाली को बेहतर बनाने और भ्रष्टाचार में कमी के उद्देश्य से के लिए उसका कंप्यूटरीकरण कर दिया। नागरिकों के लिए भी अपने कर और बिलों का भुगतान करना आसान हो गया क्योंकि पूरी प्रणाली को विकेंद्रीकृत कर 11 ज़ोनल केंद्रों पर नकद कर संग्रह और पानी के बिल जमा करने का काम शुरू कर दिया। ये सभी ज़ोनल केंद्र कंप्यूटर नेटवर्क के जरिये मुख्य कार्यालय से जुड़े हैं। इंदौर नगर पालिक निगम के सचिव जे. सी. गालर बताते हैं, ''प्रमुख बात यह रही कि ऐसा करने पर निगम पर कोई खर्च भी नहीं आया क्योंकि जिस निजी कंपनी को इसका जिम्मा सौंपा गया, उसने इसे तैयार करने के साथ ही, इसे चलाने का जिम्मा भी ले लिया जिससे कि वे करदाताओं से सेवाशुल्क वसूल कर कंप्यूटरीकरण पर खर्च रकम की भरपाई कर सके। नागरिकों ने भी इसका बुरा नहीं माना क्योंकि उन्हें अपने बिलों के भुगतान की ताज़ातरीन तस्वीर तुरंत मिल पा रही है। यही नहीं, उन्हें विभिन्न लाइसेंस

फोटो: विवेक पटेरिया

सबसे ऊपर: इंदौर में पितृ पर्वत पर अपने मित्रों और रिश्तेदारों की स्मृति में लोगों ने लगाए पौधे।
बाएं बीच में: बिजली की कम खपत करने वाली ट्यूबलाइटों के इस्तेमाल से इंदौर को मार्ग प्रकाश पर 39 फ़ीसदी बिजली बचाने में कामयाबी मिली।
दाएं बीच में : इंदौर नगर निगम के कंप्यूटरीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में संपत्ति कर और पानी के बिल जमा कराते लोग।
ऊपर: इंदौर में शुरू की गई नवीनतम तकनीक वाली बसें।

तथा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे कागजात जल्दी मिलने लगे हैं।''

यूएसएड के प्रोग्राम मैनेजर और शहरी प्रबंधन टीम लीडर एन. भट्टाचार्जी कहते हैं, ''किसी भी शहरी प्रबंधन सुधार पहल... की सफलता वहां के निकाय अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की इच्छाशक्ति और तालमेल पर निर्भर करती है। इंदौर इस मामले में बहुत बढ़िया उदाहरण है।''

इस परियोजना के तहत इंदौर नगर निगम ने जन भागीदारी के तहत रहवासी संघों के साथ मिलकर शहर की बस्तियों में 150 किलोमीटर लंबी सीमेंट की सड़कें बनाई हैं। इसमें लगभग एक तिहाई राशि का योगदान इलाके में रहने वाले लोगों ने किया है। यूएसएड कार्यक्रम ने निगम योजनाओं में लोगों की भागीदारी पर ज़ोर दिया था।

शहर में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठा नागरिक भागीदारी प्रयास एक निर्जन पहाड़ी को लोगों के सहयोग से हरा-भरा बनाने का है। यहां लोगों ने परलोक सिधार चुके अपने संबंधियों की स्मृति में 251 रूपये देकर पौधे लगवाए। उमा शशि शर्मा बताती हैं, ''ये सभी पौधे सुरक्षित हैं और इलाका हरा-भरा बन चुका है जिसे अब पितृ पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहां अब तक 15 हज़ार से ज़्यादा वृक्ष लग चुके हैं और खास बात यह है कि निगम को अपनी ओर से ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ा।'' इसके अलावा शहर में 150 पार्क विकसित किए गए हैं।

यूएसएड कार्यक्रम के जरिये इंदौर में शहरी प्रबंधन के तौरतरीके बदलने की पहल तो हुई ही, साथ ही इसका नाता कुछ समय के लिए यूएसएड की रिसॉर्स सिटी और सिटी लिंक्स परियोजना के तहत अमेरिका के गारलैंड, टेक्सास शहर से भी स्थापित हुआ। गारलैंड आकार के लिहाज से इंदौर से सिर्फ छह वर्गमील ही बड़ा है हालांकि आबादी इंदौर के मुकाबले काफी कम है। यूएसएड शहरी प्रबंधन परियोजना के प्रमुख शहरी प्रबंधन सलाहकार चेतन वैद्य के अनुसार इंदौर से गए विशेषज्ञ दलों ने गारलैंड की बजट और कर प्रणाली के जरिये अपनी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जबकि गारलैंड ने इंदौर नगर निगम की विकेंद्रीकरण योजना और अपर्याप्त मूल सुविधाओं से निपटने की रणनीति के बारे में जानकारी ली। वैद्य खुद भी मार्च 2003 में इसके तहत गारलैंड गए थे। 2002-03 से 2004-05 तक चली इस परियोजना के तहत इंदौर से तीन दल गारलैंड गए जबकि इतने ही दल गारलैंड से इंदौर आए। इसके लिए धनराशि यूएसएड की ओर से प्रदान की गई।

जहां तक अमेरिकी सहयोग का सवाल है, यूएसएड ने इंदौर नगर निगम को सड़क प्रकाश व्यवस्था का खर्च कम करने के लिए बिजली का ऑडिट कराने में भी मदद की। इससे पता चला कि बेहतर ट्यूबलाइटों के बूते 39 फीसदी बिजली बच सकती है। इसके बाद एक निजी कंपनी ने बेहतर ट्यूब और उपकरण लगाए जिसका खर्च कंपनी ने 27 महीनों तक होने वाली बिजली बचत के 80 फ़ीसदी हिस्से को लेकर पूरा किया।

भारत-अमेरिकी शहरी विकास प्रबंधन सितंबर 2008 तक चलेगा। अब तक के नतीजे क्या कहते हैं? शहरी प्रबंधन परियोजना के मुखिया बेकर कहते हैं, ''मैं संतुष्ट हूं। हमारे द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदुओं को नेहरू शहरी नवीकरण मिशन में शामिल किया गया है।'' अगले सात सालों में नेहरू शहरी मिशन के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये आवंटित होंगे। इसका फायदा वे ही शहर ज़्यादा उठा पाएंगे जिनके स्थानीय निकाय मजबूत होंगे और जो प्रबंधन के गुर सीख चुके होंगे। इंदौर ने इस दौड़ में खुद को आगे कर इस इसका संकेत दे दिया है।

इस लेख के बारे में अपने विचार editorspan@state.gov पर भेजिए।